

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र में स्टार्टअप्स की सरकारी योजनाएं

रूपसी तिवारी*, प्रतीक्षा पांडा, ललिता द्विवेदी***** और **त्रिवेणी दत्त******

“भारत नवाचार, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में अपने नागरिकों को अनेक अवसर भी प्रदान कर रहा है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में तीसरे स्थान पर है। भारत ने स्टार्टअप्स के क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान 12 से 15 प्रतिशत की लगातार वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। भारत में नवाचार केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। स्टार्टअप्स 56 विविध प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। 29 दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 81 यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्य 274.17 अरब डॉलर है। इनमें से 44 यूनिकॉर्न केवल 2021 में ही उभरे हैं, जिनका कुल मूल्य 89.17 अरब डॉलर है। इस तरह वर्ष 2021 देश के लिए एक रिकॉर्ड वर्ष रहा है। वर्ष 2020 और वर्ष 2019 में क्रमशः 10 और 9 यूनिकॉर्न थे। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 58 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। स्टार्टअप्स ने कृषि क्षेत्र में विकास तथा नवीनीकरण को अत्यधिक प्रेरित किया है। व्यापक महामारी के बावजूद, एग्रीटेक स्टार्टअप्स ने वर्ष 2020 में 30 सौदों के माध्यम से 152 मिलियन डॉलर की फंडिंग (वित्त पोषण) हासिल की है।”

*प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी एटिक; ***सीनियर रिसर्च फैलो; ****निदेशक, भाकृअनुप–भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर; **सहायक प्राध्यापक, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, रामपुरा फूल, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (गड़वासु), लुधियाना

पशुधन उत्पादन को कृषि क्षेत्र के शॉक एब्जार्बर (प्रघात अवशोषक) के रूप में भी जाना जाता है। पशुधन क्षेत्र कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4.11 प्रतिशत का योगदान देता है। इसका मूल्य 9 ट्रिलियन भारतीय रुपये से अधिक है। छोटे किसानों की सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन उत्पादन एक प्रमुख संपत्ति है। वर्तमान में ज्यादातर उत्पादन

गरीब किसानों, जिनके पास संसाधनों की कमी है, द्वारा ही किया जाता है। इसमें उन्नत तकनीकों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत में पशुधन उत्पादों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है इसलिए मांग को पूरा करने के लिए इस उद्योग को व्यावसायिक अथवा स्टार्टअप्स स्वरूप में बदलने की आवश्यकता है। लिसियस, फ्रेश टू होम, स्टेलेप्स, एनीमल, एगोज, एक्टिवक्स एनिमल हैल्थ टेक्नोलॉजीज, काउपैथी पशुधन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ भारतीय स्टार्टअप हैं। पशुधन फार्मिंग, नस्ल सुधार, पशु चारा उद्योग, कुक्कुट पालन, शूकर पालन, डेरी पालन, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन इत्यादि क्षेत्रों में आजीविका के अत्यधिक अवसर सृजित हो रहे हैं।

उद्यमिता एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

भारत सरकार ने उद्यमिता, स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए रोमांचक कार्यक्रमों की शुरूआत की है। स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और पोषित करने वाली नीतियां और रूपरेखा (फ्रेमवर्क) बनाने के लिए स्टार्टअप्स इंडिया ने एक्शन प्लान लॉन्च किया है। भारत सरकार ने उन योजनाओं के लिए 9800 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई है, जो वर्ष 2021-22 से लेकर अगले 5 वर्षों तक किसानों तथा किसान संगठनों को लाभान्वित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों, राज्य सहकारी समितियों, वित्तीय संस्थानों, बाहरी फंडिंग एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों द्वारा पशुधन क्षेत्र में 54,618 करोड़ का निवेश किया जाएगा।



व्यावसायिक कुक्कुट उत्पादन

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल

एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज

स्टार्टअप्स इंडिया के साथ साझेदारी में कृषि मंत्रालय ने कृषि-तकनीक स्टार्ट-अप्स के लिए वर्ष 2017 में इस क्षेत्र के 12 समस्या क्षेत्रों के आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान के लिए कृषि ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है।

नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आरकेवीवाई-रफ्तार योजना)

यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक अनूठी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा बिजनेस इन्क्यूबेशन प्रणाली को विकसित करके कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ये स्टार्ट-अप्स विभिन्न श्रेणियों जैसे कृषि-प्रसंस्करण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आरटीफिशियल इंटेलीजेंस), अपशिष्ट से धन, डेरी, मत्स्य पालन, डिजिटल कृषि तथा कृषि मशीनीकरण आदि के अंतर्गत आते हैं। देशभर से 24 आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) स्थापित किए गए हैं। एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन, आरएबीआई इनक्यूबेटीज की सीड स्टेज वित्तीय सहायता, कृषि उद्यमियों के लिए प्री-सीड स्टेज की वित्तीय सहायता, इस योजना के मुख्य घटक हैं।

एग्री इंडिया हैकाथॉन

एग्री इंडिया हैकाथॉन कृषि संबंधी संवाद (सुझाव व प्रोत्साहन) प्रस्तुत करने और कृषि में नवाचारों को गति देने के लिए सबसे बड़ी आभासी (वर्चुअल) सभा है।

कृतज्ञ

कृतज्ञ अर्थात् कृषि तकनीकी ज्ञान। इस कार्यक्रम का आयोजन छात्रों/प्राध्यापकों/उद्यमियों/नवोन्मेषकों और अन्य लोगों को भारत में पशुधन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए और अपने अभिनव दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।

कृषि में उद्यमियों के विकास के लिए पहल (आईडीईए)

इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि-व्यवसाय के प्रयासों को बढ़ावा देना और इसको एक लाभदायक उद्यम के रूप में स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।

छात्रों के लिए सरकारी योजनाएं

भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों और प्राध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां निर्धारित की गई हैं जैसे:-



व्यावसायिक शूकर पालन

पशुपालन और डेरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेरी मंत्रालय की पहल

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में, पशुपालन और डेरी विभाग ने डेरी एवं मांस प्रसंस्करण व उत्पाद विविधीकरण के लिए बुनियादी ढांचे तथा पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सेक्शन 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंचरना विकास कोष की शुरूआत की है।

ई-गोपाला ऐप

किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म तथा उच्च उत्पादकता व गुणवत्ता वाले मवेशी खरीदने के लिए बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ई-गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। यह कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं तथा टीकाकरण भी उपलब्ध करवाता है। यह किसानों को किफायती व उच्च गुणवत्ता वाले उपचार व पशु पोषण संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से पशुपालन और डेरी विभाग दुग्ध उत्पादक कंपनियों और दुग्ध सहकारी समितियों के 1.5 करोड़ डेरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है।

डेरी उद्यमिता विकास योजनाएं

इसमें बैंकिग योग्य परियोजनाएं हैं, जिनमें दूध उत्पादन में वृद्धि, खरीद, संरक्षण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

पशुपालन स्टार्टअप्स ग्रेंड चैलेंज

इसके अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में डीएएचडी द्वारा कुल 12 स्टार्टअप्स को 1.02 करोड़ रुपये का नकद अनुदान दिया गया। इनका प्रमुख लक्ष्य पांच समस्या क्षेत्रों के लिए एक विशिष्ट समाधान निकालना था। इनमें मूल्यवर्द्धित उत्पाद, दूध में मिलावट को खत्म करना, नस्ल सुधार व पशु पोषण, ई-कॉमर्स समाधान तथा उत्पादों की क्षमता जांच करना शामिल है। चुनौती का दूसरा चरण वर्ष 2021 में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 के रूप में शुरू किया गया है।

डेरी निवेश त्वरक (एक्सीलरेटर)

पशुपालन और डेरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार, ने भारतीय डेरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने की दिशा में अपने निवेश सुविधा प्रकोष्ठ (इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल) में डेरी निवेश त्वरक (डेरी इनवेस्टमेंट एक्सीलरेटर) की स्थापना की है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)

देसी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) लागू किया जा रहा है। यह योजना 2400 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक की अम्ब्रेला परियोजना 'राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना' के तहत भी जारी है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

पशुपालन और डेरी विभाग, भारत सरकार रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना को लागू कर रही है।



व्यावसायिक बकरी पालन

नवाचार और स्टार्टअप नीति वर्ष 2019

उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के छात्रों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप्स नीति वर्ष 2019 एक मार्गदर्शक ढांचा है। यह संस्थानों को नवाचार और उद्यमिता संबंधी गतिविधियों में उनके छात्रों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों को सक्रिय रूप से संलग्न करने में सक्षम बनाता है। इस नीति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों के लिए ऐसा वातावरण विकसित करें, जिसमें छात्र नवाचार, उद्यमिता और उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान के बुनियादी ढांचे, प्राध्यापकों की सहायता तथा संस्थान द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के माध्यम से अपनी डिग्री लेने के साथ-साथ अपनी स्टार्टअप कंपनी को इंक्यूवेट तथा विकसित कर सकें। यह नीति सुनिश्चित करती है कि छात्र विविध उद्यमशील गतिविधियों में संलग्न होकर अपने नवाचारों को स्टार्टअप का रूप दे सकें।

नई शिक्षा नीति 29 जुलाई, वर्ष 2020

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं पर ध्यान देना है। यह शिक्षा नीति



भूसा उत्पादन इकाई

छात्रों को बहुविषयक शिक्षा देने पर आधारित है। इसका उद्देश्य छात्रों को रचनात्मकता तथा नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करना है। यह नीति तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल देती है। इसके अंतर्गत छात्रों के लिए कई निकास विकल्प बनाये गये हैं। छात्रों को चार वर्ष में बहुविषयक स्नातक डिग्री दी जायेगी। अगर छात्र किन्हीं कारणों से चार वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वे तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, दो वर्ष बाद डिप्लोमा तथा एक वर्ष के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस नीति के अनुसार छात्रों के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार नई शिक्षा नीति छात्रों के बहुआयामी विकास के साथ-साथ उद्यमिता के विभिन्न अवसर प्रदान करेगी।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल), अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) (नीति आयोग)

इनका उद्देश्य उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना और भारत में एक मिलियन इनोवेटर्स विकसित करना है। अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग द्वारा संचालित देश में नवाचार और उद्यमिता



वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन इकाई



पैरावेट द्वारा पशु स्वास्थ्य सेवा

महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाएं

सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष रूप से विभिन्न नीतियां, सब्सिडी, छूट और प्रति पूर्तियां बनाई हैं। महिला उद्यमियों द्वारा अपना खुद का व्यवसाय आसानी से शुरू करने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।

- **महिला उद्यमिता मंच:** सरकार के नीति आयोग ने महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष पोर्टल, महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है। इस मंच पर महिला उद्यमी स्टार्टअप उद्योग के विशेषज्ञों और पेशेवरों से सहायता ले सकती है।
- **स्टार्टअप इंडिया:** इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के स्वामित्व वाले स्टार्टअप्स का प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न अवसर और मंच प्रदान करती है।
- **महिलाओं के लिए ऋण योजनाएं:** भारत सरकार, विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई, कुछ क्रेडिट नीतियों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जैसे-अन्नपूर्णा योजना, नारी शक्ति योजना, महिला विकास योजना, देना शक्ति, उद्योगिनी योजना, सेंट कल्याणी योजना, महिलाओं के लिए मुद्रा योजना, महिला उद्यम निधि योजना, भारतीय महिला बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक ऋण (एमएसएमई), व्यापार से संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना।



पशु एम्बुलेंस सेवा

की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है और इसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। इस दिशा में एआईएम ने स्कूलों में समस्या-समाधान की ओर केन्द्रित एक अभिनव मानसिकता बनाने और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी और एमएसएमई क्षेत्रों में उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इस मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब (स्कूलों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए); अटल इनक्यूबेशन सेंटर (विश्वविद्यालयों, संस्थानों व कंपनियों में नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए); अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (टियर 2, 3 शहरों, जिलों, आदिवासी, पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए); अटल न्यू इंडिया चैलेंज (राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाले उत्पादों को बनाने के लिए); ए.आर.आई.एस.ई.ए.एन.आई.सी. चैलेंज (स्टार्टअप/एमएसएमई उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए) तथा मेंटर इंडिया-द मेंटर्स ऑफ चेंज (सलाहकार (मेंटर) नियुक्ति और प्रबंधन के लिए) आदि कार्यक्रमों को लांच किया गया है।

विकास और नवाचारों के दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (निधि) (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

एनआईडीएचआई (निधि) एक व्यापक कार्यक्रम है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा युक्तियों (योजनाओं) और नवाचारों (ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित) को सफल स्टार्टअप्स में बदलने के लिए शुरू किया गया

सारणी: पशुपालन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजना	वर्ष	वेबसाइट/लिंक
1	राष्ट्रीय कामधेनु आयोग	2019	www.kamdhenu.gov.in www.kamdhenu.blog
2	विशिष्ट पशुधन क्षेत्र पैकेज	2021.2022	https://pib.gov.in/PressRelese Detailm.aspx?PRID=k1735928
3	पशुपालन अवसंरचना विकास कोष	2020	www.dahd.nic.in
4	ई-गोपाला ऐप	2020	www.dahd.nic.in
5	किसान क्रेडिट कार्ड	1998	www.dahd.nic.in
6	डेरी उद्यमिता विकास योजना	2010	www.startupindia.gov.in, www.nabard.org
7	पशुधन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0	2019	www.mygov.in
8	डेरी निवेश त्वरक	2021	www.dahd.nic.in
9	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	2014	www.dahd.nic.in
10	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	2014-2015	www.dahd.nic.in
11	एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज	2021	www.startupindia.gov.in
12	• अटल इनोवेशन मिशन • अटल टिंकरिंग लैब • अटल इन्क्यूबेशन सेंटर • अटल कम्यूनिटी ईनोवेशन सेंटर	2016	www.aim.gov.in
13	अटल न्यू इंडिया चैलेंज	2018	www.aim.gov.in
14	अराईज अनिक चैलेंज	2020	www.aim.gov.in
15	मेंटर इंडिया-द मेंटर्स ऑफ चेंज	2014	www.aim.gov.in
16	कृतज्ञ	2021	www.icar.org.in
17	आईडिया (कृषि में उद्यमियों के विकास के लिए पहल)	-	www.startupindia.gov.in
18	महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी)	2017	www.startupindia.gov.in
19	स्टार्टअप इंडिया	2016	www.startupindia.gov.in
20	डी.बी.टी. बायोकेयर	2011	www.dbtindia.gov.in
21	डी.एस.टी. किरण	2014	www.dst.gov.in
22	मुद्रा योजना	2015	www.mudra.org.in
23	महिला उद्यम निधि योजना	-	www.laghu-udyog.gov.in
24	ट्रेड (व्यापार से संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना)	2014-15	www.startupindia.gov.in
25	नवाचार व स्टार्टअप नीति	2019	www.startupindia.gov.in
26	निधि • नीधि-जीसीसी • निधि-प्रयास • निधि-(आंत्रप्रेन्योर इन रेजीडेंस) • स्टार्टअप्स निधि • निधि प्रौद्योगिकी बिजनेस इक्यूबेट • निधि एक्सीलरेटर	2016	www.indiascienceand technology.gov.in



बिल्लियों की ब्रीडिंग

है। इसका प्रमुख उद्देश्य है: आईईडीसी/न्यू जनरेशन आईईडीसी कार्यक्रम में छात्र नवाचारों को व्यावसायिक चरण तक ले जाना, छात्र स्टार्टअप को बढ़ावा देना, प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करके एक योजना से (विचार/योजना) एक प्रारूप में बदलने की यात्रा को तेज करना। इसके 8 घटक हैं, जो एक उभरते हुए स्टार्टअप्स के प्रत्येक चरण को मजबूती प्रदान करते हैं:

- **निधि जीसीसी:** नवाचारों/नई प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए बड़ी चुनौतियां और प्रतियोगिताएं आयोजित करता है।
- **निधि प्रयास:** युवा और महत्वाकांक्षी नवोन्मेषकों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा और गति देता है। यह किसी योजना से एक प्रारूप तक के चरणों में सहयोग देता है।
- **निधि निवास में उद्यमी (आंत्रप्रेन्योर इन रेजीडेंस):** जोखिम को कम करने



मांस के अचार का उद्योग

के लिए सहायता प्रणाली।

- **निधि प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटर (टीबीआई):** नवोन्मेष को स्टार्ट-अप में बदलता है।
- **निधि त्वरक (एक्सीलरेटर):** केंद्रित हस्तक्षेप के माध्यम से एक स्टार्ट-अप की गति में वृद्धि करने में मदद करता है।
- **निधि बीज समर्थन प्रणाली (निधि-एसएसएस):** प्रारंभिक चरण में निवेश प्रदान करता है।
- **निधि उत्कृष्टता केंद्र:** स्टार्टअप को वैश्विक बनाने में मदद करने के लिए एक विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करता है।



पशु आहार उद्योग

स्टार्टअप और एफपीओ

वर्तमान में, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 600 से 700 एग्रीटेक स्टार्टअप हैं जो कृषि-मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। विपणन क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स किसानों और छोटे कृषि खाद्य ऑपरेटरों को सशक्त बना रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को एक बेहतर सौदा दे रहे हैं। निन्जाकार्ट, देहात और क्रॉफार्म (ओटिपी) कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं, जो कृषि बाजार को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों को सशक्त ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि उपनगरों में स्थानीय/किराना स्टोर से भी हाथ मिला रहे हैं। दूसरी ओर ये नेटवर्क उन बड़े फर्मों को सीधा लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें थोक उत्पादन की आवश्यकता है और जो किसानों से जुड़ने में सक्षम नहीं हैं। स्टार्टअप एफपीओ साझेदारी को मजबूत करना देश में कृषि-स्टार्टअप उद्योग के लिए भविष्य का यंत्र हो सकता है। यह प्रणाली न केवल बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत उत्पादकों के विकास का वादा करेगी, बल्कि बढ़ती अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करेगी, रोजगार पैदा करेगी और जनता को आजीविका सुरक्षा प्रदान करेगी।



स्वान (कुत्ता) ब्रीडिग फार्म

भारत में आज का समय युवा व महिला उद्यमियों द्वारा अपने निजी व्यवसाय को स्थापित व विकसित करने के लिए एक सुनहरा मौका है। सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि व पशुधन क्षेत्र में युवाओं तथा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार कई स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से युवाओं तथा महिला उद्यमियों को उनके नवाचारों को प्रारूप तैयार करके इन नवाचारों को व्यावसायिक स्तर पर पहुंचाने के लिए कुछ शुरूआती सहायता राशि देकर उनकी मदद करती है। सरकार ने छात्रों के लिए भी इस क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरूआत की है, जिसकी मदद से छात्र इस क्षेत्र में भी अपना करियर बनाने में सफल हो सकते हैं। नई शिक्षा नीति भी इन सब बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कृषि व पशुधन क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए भी अपना व्यवसाय शुरू करने व बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष रूप से केवल महिलाओं के लिए कई स्टार्टअप व योजनाएं शुरू की हैं। सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले अवसरों की कोई कमी नहीं है। परंतु इन अवसरों तथा स्टार्टअप्स की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे वे इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अतः इस लेख के माध्यम से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तथा स्टार्टअप्स की विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जो युवा व महिला उद्यमियों, किसानों व पशुपालकों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। ■